मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- रिलायंस ने ओएनजीसी के कुएं से हज़ारों करोड़ की गैस चुरायी, तो क्या हुआ ? 3
- गुड़गांव व मेवातः नाम खत्म करने के पीछे सांप्रदायिक राजनीति 4
- केक की औकात नहीं तो सूखी रोटी से काम चला! 5
- ईएसआई निगम की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये संघर्ष करें 8

वर्ष 29 अंक 11 फरीदाबाद, शनिवार 16-30 अप्रैल 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

135 एकड़ ज़मीन लूटने में जुटे नेता व अफ़सर

महीनों से धरने पर बैठे पीड़ित, कोई सुनाई नहीं

रॉबर्ट वाड्रा के फ़र्जी ज़मीन सौदों की जांच के लिये मनोहर लाल खट्टर सरकार ने न्यायिक आयोग बैठा रखा है। जबकि इसी सरकार की नाक के ऐन नीचे 135 एकड़ ज़मीन को भू.माफ़ियाओं का गिरोह राजनीतिक संरक्षण में हड़पता जा रहा है। इस गिरोह को न अपनी जेब में रखे प्रशासन की परवाह है और न न्यायालय का डर। यहां तक कि वे अपने रास्ते में आये सबसे बड़े रोड़े पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव को हटवाने में भी सफ़ल हो गये हैं।

मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद ब्यूरो

दिल्ली से सटे फ़रीदाबाद के थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र में दिल्ली के करीब एक हज़ार सरकारी कर्मचारियों ने एक रिहायशी कॉलोनी बनाने हेतु 1967 में कुल 135 एकड़ ज़मीन खरीदी। इसके लिये इन लोग़ों ने ग्रीन एस्टेट एवं एच आर ई प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन का गठन किया था। सरकारी नियमानुसार कॉलोनी निर्माण हेतु डीटीपी (ज़िला टाउन एंड कंट्री प्लानर) से स्वीकृति मांगी गयी। डीटीपी ने अड़ंगा लगाया कि एसोसिएशन दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इसे दूर करने के लिये एसोसिएशन ने नवीन को-आप्रेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी बना कर हरियाणा में रजिस्टर करा ली। लेकिन अड़ंगे लगाने वाले भ्रष्ट अफ़सरों ने एक के बाद एक बहानेबाज़ी करके सोसायटी को कॉलोनी एवं मकान बनाने की स्वीकृति नहीं दी।

अंधी बहरी सरकार को ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनता है

सन् 1996 तक यह खेल चलता रहा। इस बीच दिल्ली से सटी इस ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे। आज वहां 5 करोड़ में भी एक एकड़ ज़मीन उपलब्ध नहीं है। इन हालात में स्थानीय नेताओं के भेस में घूमते भू-माफ़ियाओं ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ कर 135 एकड़ के इस भू-खंड को हड़पने की कार्य-योजना बनाई।

सर्वप्रथम भूखंड की देख-रेख करने वाले सोसायटी के अध्यक्ष रामलुभाया व सचिव जसबीर सिंह को दिनांक 1.9.96 को, जब वे इस भूखंड पर आये तो इतनी बुरी तरह से मारा-पीटा गया कि दोनों महीनों तक अस्पताल में पड़े रहे। जसबीर तो बरसों तक अपने पैरों पर चलने लायक नहीं हो सका। थाना सराय ख्वाज़ा में एफ़आईआर दर्ज कराई गयी। पुलिस चूंकि खुद भू-माफ़ियाओं से मिली हुई थी, इस लिये हल्की-फुल्की धारायें लगा कर मामले को सस्ते में निपटा दिया गया। दहशतज़दा सोसायटी सदस्यों की कई बरस तक भूखंड की तरफ़ झांकने की हिम्मत न हुई। यही भू-माफ़िया चाहते थे। स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भू-माफ़ियाओं ने समय-समय पर सोसायटी की 3 फ़र्जी कार्यकारिणी बना कर फ़र्जी अध्यक्ष व सचिव खड़े कर लिये तथा इस भूखंड में अवैध रूप से प्लॉट काट-काट कर बेचने शुरू कर दिये।

जिस डीटीपी कार्यालय ने 30 साल तक सोसायटी वालों को विधिवत रूप से एक वैध कॉलोनी नहीं बनाने दी, उसी डीटीपी को इस अवैध कॉलोनाइजेशन एवं फ़जीवाड़े से कोई तकलीफ़ नहीं थी; लिहाज़ा देखते ही देखते 50 गज़ से लेकर 100, 200, 500 गज़ तक के प्लॉट वहां ऐसे बिकने लगे जैसे मंदिर का प्रसाद बंटता है। खरीदने वाले अधिकांश गरीब एवं श्रमिक वर्ग के लोग ही थे। बेचने वाले फ़र्जी मालिक इतने बेखौफ़ होकर प्लॉट बेच रहे थे जैसे कोई असली मालिक बेचता है।

शेष पेज दो पर

भू-माफ़ियाओं ने पाल रखी हैं तीन देवियां

इतनी बड़ी नवीन नगर जायदाद हजम करने के अनेक हथकंडों में से एक हथकंडा तीन देवियों का भी है। पूरे क्षेत्र में गुंडागर्दी के लिये जानी-मानी इन देवियों के नाम हैं-नीरज राणा, मंजू व रेखा। इन देवियों के लिये वहीं पर बाकायदा एक शनि देव मन्दिर भी स्थापित किया गया है। इन देवियों को संचालित करने के लिये इस मंदिर में एक पाखंडी पुजारी भी बैठा रखा है। इन तीनों देवियों की पुलिस महकमे में पूरी पकड़ है। पुलिस को पैसे देने से लेकर हर प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने में ये माहिर हैं। सोसायटी का कोई सदस्य यदि ज़मीन पर आ जाये तो ये मारने-पीटने को दौड़ती हैं। तीनों अच्छी फ़ाइटर बताई जाती हैं। आखिरी हथियार के तौर पर अपने कपड़े स्वयं फ़ाड़ कर दूसरों पर दोष लगाने से भी नहीं चूकतीं।

एक बार किसी पुलिस वाले ने 'गलती' से या किसी दबाव में एक अवैध निर्माण को रूकवा दिया और निर्माण करने वाले को पकड़ लाया तो ये तीनों चौकी में पहुंच गयीं। चौकी में इन्होंने वो हंगामा किया व अश्लील गालियां पुलिस वालों को दीं जो कोई सभ्य जन सुन नहीं सकता। देवियां चिल्ला-चिल्ला कर साफ़ कह रही थीं कि फ़लां-फ़लां दिन तुमको इतना पैसा दिया उसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गयी निर्माण रोकने व कराने वाले को पकड़ने की ? पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उनके विरुद्ध कुछ कर पाने की।

ऐसे ही बुलंद हौंसलों के दम पर नवम्बर 2015 में एक दिन सोसायटी के सचिव पुंज ने जब अपनी ज़मीन पर होते एक अवैध निर्माण की फ़ोटो अपने मोबाइल से लेली तो इन देवियों ने उनका मोबाइल छीन कर तोड़ दिया और पुंज की अच्छी-खासी पिटाई कर दी। पुंज जब शिकायत करने चौकी पहुंचे तो ये भी तीनों साथ-साथ वहां पहुंच गयीं। चौकी में ही पुलिस के सामने इन्होंने अपने कपड़े फ़ाड़ लिये तथा पुंज पर आरोप लगाते हुए उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। पुंज जब शिकायत करने सी पी सुभाष यादव के पास पहुंचे तो ये वहां पहले से ही खड़ी थीं। सी पी ने दोनों को सुना। सारी हकीकत समझने के बाद उन्होंने इन देवियों को खूब हड़काया-धमकाया। लेकिन इससे आगे वे भी कुछ कर नहीं पाये।

ख़बर दार

जात ही पूछो खट्टर से.....

हरियाणा की राजनीति में जातिवाद की हमेशा से भूमिका रही है। तमाम उत्तर भारत में जिस अंदाज़ से गंगा-जमुनी संस्कृति की बात होती है उसी तरह हरियाणा में 36 बिरादरी का ढोल पीटा जाता रहा है। गत विधानसभा चुनाव तक भाजपा भी यही राग अलाप रही थी। खट्टर सरकार बनने के बाद उन्होंने किसान बिरादरियों को बांटने का जिम्मा उठा लिया तथा नारा दिया 35 बिरादरी बनाम जाट। इसके पीछे वजह यह रही कि केन्द्र व राज्य में सत्तासीन होते हुए भी न तो जाट आरक्षण का अपना वादा पूरा कर पा रहे थे और न ही फ़सलों की वाजिब कीमत तय करने का स्वामीनाथन फ़ार्मूला लागू करने में उनकी कोई दिलचस्पी थी। जातिवाद की पतवार से चल रही खट्टर की नैया क्या मझदार से निकल पायेगी-पढ़िये खट्टर का काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो.-खट्टर साहब आपकी भाजपा और आरएसएस तो हिन्दू एकता की कसमें खाते हैं। अब हरियाणा में लोग आपको पाकिस्तानी कहने लगे ?

खट्टर-पाकिस्तानी तो खैर हम पुराने हैं ही, उसका गम तो रहेगा ही। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज सिर्फ़ जाट ही क्यों हमें पाकिस्तानी कह रहे हैं। यानी हरियाणा में जातिवादी ध्रुवीकरण का हमारा खेल कुछ तो रंग ला रहा है। चुनावी फ़सल तो इसी तरह कटेगी, किसानी फ़सल काट पाना तो हमारे बस का नहीं।

म.मो.-आपने जाट नाहक नाराज कर लिये। पहले ही वादे के मुताबिक आरक्षण दे दिया होता तो यह नौबत न आती।

खट्टर-अगर यह नौबत न लाई जाती तो हम 35 बिरादरी की 'एकता' का खेल कैसे खेल पाते भला ? महंगाई, रोजग़ार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर तो हम कुछ करने लायक थे ही नहीं। ऐसे में ले-दे कर साम्प्रदायिक वैमनस्य का अपना पुराना कार्ड ही नये सिरे से हमें खेलना था। इसमें तो हम माहिर हैं ही।

म.मो.-उत्तर प्रदेश में भी अगले वर्ष चुनाव होने हैं। क्या वहां नाराज जाट आपकी पार्टी को वोट देंगे ?

खट्टर-क्या मुज़फ्फ़रनगर और लव-जिहाद को भूल गये ? जरूरत महसूस हुई तो हमारे कार्यकर्ता एक और मुजफ़्फर नगर रच देंगे। फ़िर गौ माता भी तो हैं जिनके नाम पर 'हिन्दू एकता' की अलख फ़िर जगाई जा सकती है। जब हम 35 बिरादरी को बेवकूफ़ बना सकते हैं तो जाट तो होते ही बेवकूफ़ हैं।

म.मो.-हरियाणा में जितनी हिंसा व लूटपाट हुई है उसे लेकर आपको कोई अफ़सोस नहीं ? स्वयं आपकी सरकार ने एक हज़ार करोड़ के नुकसान का दावा किया है। यह रकम विकास कार्यों में भी तो लगाई जा सकती थी ?

खट्टर-विकास कार्यों से भी तो वोट हासिल करने होते हैं। अब हमारा क्या बिगड़ गया। हमारे वोट तो अब भी पक्के ही हुए हैं। कान हमेशा सीधे पकड़ो, यह जरूरी तो नहीं।

म.मो.-लेकिन आपके समर्थकों के हाथ-पांव टूटे और उनके घर व्यापार नष्ट हुए ? क्या इससे उनका भरोसा आपकी सरकार से उठ नहीं गया होगा ? उन्होंने बड़े अरमानों से आपको मुख्यमंत्री बनाया था। अब क्या मुंह लेकर आप उनके पास जायेंगे ?

खट्टर-मुंह नहीं मुआवज़ा लेकर। लोग चोट को कम याद रखते हैं, चोट पर नोटों के मरहम को कहीं ज़्यादा। यानी चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। देखना ये सभी एक स्वर से कहेंगे-खट्टर साहब ने हमें बसा दिया।

म.मो.-आपके समर्थक जाटों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं ?

खट्टर-यह तो पार्टी स्तर पर पहले ही तय हो गया है कि पाकिस्तान तो केवल मोदी साहब ही जायेंगे।

हरियाणा में जातिवादी रंग में रंगे जाँच कमीशन भी

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक-एक कर अपने सभी जातिवादी पत्ते खोल दिए हैं। आन्दोलन को शुरू से ही जातिवादी रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी थी, अब उसकी जाँच की आड़ में भी जातिवादी ध्रुवीकरण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है।

अंधी हिंसा के उस आतंकी दौर में आम जन की जान-माल-इज्जत की सुरक्षा से हाथ खींचने वाली भाजपा सरकार ने सबसे पहले तो प्रकाश सिंह आयोग बनाया जिसके मुखिया ने दावा किया है कि प्रदेश की पुलिस जातीय आधार पर बंटी हुयी थी और इसलिए लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकी। यानी सारा दोष हुआ पुलिस का और सरकार बेदाग बरी ! प्रकाश सिंह से कोई यह पूछे कि हरियाणा पुलिस अचानक जाति आधार पर कैसे काम करने लगी ? क्या यह खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली का असर है या प्रकश सिंह को भी देखने के लिए जाति का चश्मा पहना दिया गया है।

शेष पेज दो पर